जल समाचार

पवन कुमार

• जल चेतना पत्रिका को प्रदान किया गया राजभाषा कीर्ति पुरस्कार- प्रथम

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान विगत पांच वर्षों से हिंदी में जल चेतना नामक तकनीकी पत्रिका प्रकाशित कर रहा है इसमें जल संबंधी समस्याओं एवं उनके निवारण के साथ-साथ सामान्य जानकारियों को भी शामिल किया जाता है। इस पत्रिका के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इसकी 5000 प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं और पाठकों को इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मुझे यह जानकारी देते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि हमारी इस पत्रिका को वर्ष 2015-16 के लिए ''क'' क्षेत्र के कार्यालयों की श्रेणी में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' (प्रथम) के लिए चयनित किया गया। यह पुरस्कार दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन आडिटोरियम, नई दिल्ली में प्रदान किया गया। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने इस अवसर पर राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जल चेतना के माध्यम से संस्थान और जल विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच राजभाषा के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस शुभ अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे। पुरस्कार श्री राजदेव सिंह, निदेशक एवं संरक्षक, जल चेतना ने प्राप्त किया। यह पुरस्कार हमारे लिए बड़े गौरव की बात है तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में संस्थान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संपादन कार्य से जुड़े समस्त पदाधिकारीगण, मुख्य संपादक, संपादक, सह-संपादक, परामर्श दाता, विभागेत्तर परामर्शदाता के साथ-साथ समस्त विद्वत रचनाकार इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को आयोजित हिन्दी मास समारोह में मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महामंत्री पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, हरिद्वार तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. एम. आर. सकलानी पूर्व सचिव उत्तराखंड हिन्दी अकादमी एवं पूर्व निदेशक उत्तराखंड भाषा संस्थान, देहरादून एवं निदेशक राजसं के कर कमलों द्वारा तकनीकी पत्रिका 'जल चेतना' के समस्त संपादक मंडल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के जाने माने व्यक्ति उपस्थित थे।

• ग्रामीण महिलाओं एवं स्कूली बच्चों के लिए जल तथा जल संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा महिलाओं तथा स्कूली बच्चों को जल एवं जल संरक्षण विषय पर जानकारी देने के लिए शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल सिकन्दरपुर भैंसवाल, भगवानपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती ममता राकेश, माननीय विधायक भगवानपुर एवं श्री राव फरमूद, माननीय अध्यक्ष घाड विकास समिति, (कैबिनेट मंत्री स्तर) द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान की वैज्ञानिक एवं संयोजिका डॉ. रमा मेहता द्वारा जल एवं जलगुणवत्ता तथा श्री दिगम्बर सिंह, वैज्ञानिक द्वारा जल संरक्षण एवं जल जनित बीमारियों एवं इससे जुड़े भिन्न-भिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। श्री पी. के. उनियाल द्वारा संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए जल संरक्षण विषय पर ड्राइंग तथा कविता-पाठ और महिलाओं के लिए भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें प्रतिभागियों द्वारा बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया गया। बच्चों ने ड्राईग के माध्यम से जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यशाला में आस-पास की ग्रामीण महिलाओं तथा स्थानीय स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। निर्णायक मंडल में संस्कृति एन. जी. ओ. के अध्यक्ष श्री विनोद शास्त्री, शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल सिकन्दरपुर की निदेशक अर्चना गौड़ एवं स्वाति शर्मा, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, आनन्द स्वरूप आर्य सरस्वती मंदिर के प्रधानाचार्य डॉ. राजीव गुप्ता, अम्बुजा सीमेन्ट के पर्यावरण अध्यक्ष श्री देवेन्द्र चौहान, अभ्युदय वात्सल्य एन. जी. ओ. के संस्थापक निदेशक श्री अशोक कुमार मिश्र -क्षितिज' उपस्थित थे। माननीय मुख्य अतिथि ममता राकेश ने पानी की दिन प्रतिदिन बिगड़ती गुणवत्ता पर चिन्ता व्यक्त की साथ ही कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अनुरोध है कि वे अपना पानी शोधित करने के उपरान्त ही प्रवाहित करें। ऐसी कार्यशालाएं नियमित अंतराल पर कराई जाती रहनी चाहिए इसमें महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। इस अवसर पर कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु श्री पीयुष गौड एवं संस्थान के पी. के. उनियाल, पवन कुमार, प्रदीप कुमार सुभाष किचलू, अलका, सीमा भाटिया, आदि द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया गया।

• बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक के बारे में एन.आई.एच. करेगा प्रशिक्षित

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एन.आई.एच.) में बैंक फिल्ट्रेशन फॉर सस्टेनेबल ड्रिंकिग वाटर विषय पर पांच दिवसीय ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया गया। इसमें देश के पंद्रह राज्यों के विभिन्न संस्थानों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

संस्थान के वैज्ञानिक एवं कोर्स को-आर्डिनेटर डॉ. एन. सी. घोष ने बताया कि इस कोर्स के माध्यम से प्रतिभागियों को बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक के बारे में ट्रेंड किया गया। जर्मन से पांच विशेषज्ञ भी मुख्य वक्ता के रूप में इसमें शामिल हुए इस तकनीक का इस्तेमाल करके पानी को कम खर्चे में पीने योग्य बनाया जा सकता है। उनके अनुसार छोटे गांवों में यह तकनीक कारगर है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड आदि राज्यों से प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। डॉ. घोष ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट के तहत देश में दो साल में उन्हें इस तरह के चार ट्रेनिंग कोर्स आयोजित करवाने हैं। एन.आई.एच. में 12 से लेकर 16 सितंबर 2016 तक यह पहला कोर्स आयोजित हुआ।

• समय से पहले टूटा गोमुख ग्लेशियर

15 साल से ग्लेशियर का अध्ययन कर रहे एन.आई.एच. के वैज्ञानिकों का दावा

गोमुख ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से वैज्ञानिक हैरत में नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि यह घटना समय से पहले हो गई। आमतौर पर ग्लेशियर जुलाई के अंतिम अथवा अगस्त के पहले सप्ताह में टूटते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियरों की सेहत ठीक नहीं है। कम बर्फबारी और बढ़ते तापमान से यह नौबत आ रही है।

रुड़की स्थित राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एन.आई.एच.) की टीम वर्ष 2000 से गोमुख ग्लेशियर का अध्ययन कर रही है। एन.आई.एच. में सतही जलविज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनोहर अरोड़ा के अनुसार ग्लेशियरों का टूटना एक सामान्य घटना है, हालांकि इस बार यह कुछ जल्दी घटित हो गई। वह बताते हैं कि 15 साल पहले ग्लेशियर पर करीब साढ़े छह फीट बर्फ देखने को मिलती थी, लेकिन अब बर्फ की यह परत घटकर साढ़े चार फीट रह गई है। उन्होंने बताया कि जब ताजी बर्फ की परत पतली होगी तो मूल ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक नेगेटिव मास बैलेंस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्लेशियर बढ़ने की बजाए सिकुड़ रहा है। डॉ. अरोड़ा बताते हैं कि वैज्ञानिकों की टीम ने अपने अध्ययन में पाया कि पहले नवंबर में अच्छी बर्फबारी होने लगती थी। जबकि बीते कुछ वर्षों से बर्फबारी का यह पैटर्न फरवरी में देखने को मिल रहा है। एन.आई.एच. के निदेशक राजेदव सिंह बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में आए बदलाव को स्थायी नहीं मानते। वह कहते हैं कि यह स्थिति कभी भी बदल सकती है। तब ग्लेशियर नेगेटिव मास बैलेंस से पाजिटिव मास बैलेंस (ग्लेशियर के बढ़ने की प्रक्रिया) में आ जाएंगे।

• गंगा से चार गुना ज्यादा ग्लेशियर वाली है श्योक

गंगा से भी चार गुना अधिक ग्लेशियर वाली श्योक नदी भारत में है लेकिन उसके संसाधनों की जानकारी से अभी तक देश अछूता है लेकिन अब इस नदी के जल संसाधन और वहां जल ऊर्जा की संभावना की जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। एन.आई.एच. ने इस ओर काम करना शुरू कर दिया है।

लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक है। इस नदी का ग्लेशियर का क्षेत्र 10,810 स्क्वायर किलोमीटर है जबकि भारत की जीवनदायनी गंगा नदी का ग्लेशियर क्षेत्र मात्र 2,128 स्क्वायर किलोमीटर है। गंगा नदी से करीब चार गुना अधिक ग्लेशियर वाली इस नदी पर अभी तक न तो कोई जल विद्युत परियोजना है और न ही इस तरफ कोई ध्यान दिया गया है। फिलहाल, इस नदी से लेह में जाने वाले पर्यटकों को पानी उपलब्ध हो रहा है लेकिन इस नदी में कितना पानी है और उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इसकी जानकारी देशवासियों को नहीं है। इस नदी में मई से सितंबर तक पानी बहता है। बाकी अन्य महीनों में बर्फ जम जाती है।

ऐसे में गर्मियों में आने वाले पर्यटकों को यह नदी काफी जल उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का दल डॉ. रिनोज थैय्यन के नतृत्व में इस नदी में पानी की उपलब्धता और यहां के जल से भावी उम्मीदों के लिए आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए संस्थान ने यंत्र लगाए है।

• एक साथ 100 स्थानों से मिशन क्लीन गंगा

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने और उसके किनारों को विकसित करने के लिए मिशन फॉर क्लीन गंगा की योजनाएं तैयार हो गई हैं। इसका शिलान्यास 7 जुलाई 2016 को एक साथ देश के सौ स्थानों पर होगा। छह स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम होंगे। जिसमें हरिद्वार, पटना, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और हावड़ा शामिल हैं।

मिशन फॉर क्लीन गंगा योजना के तहत गंगोत्री से लेकर गंगासागर के बीच गंगा किनारे घाट बनाए जाएंगे और विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण होगा। इसका शिलान्यास प्रमुख स्थानों पर केंद्रीय मंत्री करेंगे, बाकी स्थानों पर नमामि गंगे की योजना के अनुसार शिलान्यास कराया जाएगा। मिशन के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए हैं। जिसमें गंगा में गिरने वाले छोटे बड़े सभी नालों के पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण शामिल है। इसके अलावा कुछ छोटे प्रोजेक्ट हैं, जिनकी शुरुआत इसी महीने से की जा रही है। मिशन फॉर क्लीन गंगा से जुड़े संजय चतुर्वेदी ने बताया कि हरिद्वार में जल संसाधन मंत्री उमा भारती और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बाकी स्थानों पर मंत्रियों का नाम अभी घोषित नहीं किया गया है। गंगा किनारे बनाए जाने वाले घाट और विद्युत शवदाह गृह के लिए केंद्रीय निर्माण एजेंसियां भी तय कर दी गई हैं।

• अब गंगा न होगी मैली, न घटेगा पानी

- ◆ 231 परियोजनाओं के साथ राज्यों में नमामि गंगे का शुभारंभ।
- ◆ औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण कचरा नदी में न जाए, इसके प्रयास होंगे।
- ◆ निर्मलता और अविरलता बनाए रखने के लिए जल्द ही आएगा अधिनियम

मोक्षदायिनी मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सात राज्यों में अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नमामि गंगे के पहले चरण का 231 परियोजनाओं के साथ शुभारंभ कर दिया। इस पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें नदी को स्वच्छ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और इसके बहाव को अवरोध मुक्त करना शामिल है।

शुरुआत नदी के किनारों को सुन्दर बनाने से होगी। साथ ही घाटों और श्मशान घाटों का निर्माण और मरम्मत भी होगी। इसी के साथ गंगा किनारे वाले पांच राज्यों में 104 स्थानों पर अधिक क्षमता वाले सीवेज बनाए जाएंगे।

• क्या होगा इस परियोजना से?

⇒ गंगा को स्वच्छ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गंगा के बहाव को अवरोध मुक्त करना शामिल है।
⇒ सफाई का पहला चरण अक्टूबर, 2016 में पूरा होगा।
⇒ दूसरा चरण उसके दो साल बाद पूरा हो जाएगा।
⇒ एप भी लांच इससे की जा सकेगी प्रदूषण निगरानी।
⇒ परियोजना के तहत उ.प्र. में 112, उत्तराखंड में 47, बिहार में 26 प.बंगाल में 20 और झारखंड में 19 योजनाएं चलेंगी। इसमें दिल्ली-हरियाणा में यमुना के लिए सात योजनाएं भी शामिल की गई हैं।
⇒ आठ बायोडायवर्सिटीज सेंटर। इन्हें ऋषिकेश, देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, साहिबगंज और बैरकपुर में स्थापित किया जाएगा।
⇒ गंगा ग्राम योजना में नदी से लगे 400 गांवों को वेस्ट मैनेजमेंट में शामिल किया जाएगा।
⇒ 30 हजार हे. इलाके में पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। 113 रीयल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन।
⇒ जोर देने के साथ शौचालयों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा।
⇒ शमशान घाटों पर भी ऐसी व्यवस्था पर जोर है ताकि अधजले या बिना जले शव नदी में न बहाए जाएं।

• गंगा की पवित्रता को बनेगा एक्ट

उत्तराखंड में नमामि गंगे के तहत 43 परियोजनाओं का शुभारंभ

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुद्धार मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाला अवजल ट्रीटमेंट के बाद भी गंगा में नहीं डालने दिया जाएगा। केंद्र सरकार गंगा की निर्मलता व अविरलता को बनाए रखने के लिए जल्द अधिनियम बनाएगी, जिसमें ऐसे कड़े नियमों और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त सजा के प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत 20 हजार करोड़ खर्च कर केंद्र सरकार गंगा पर अहसान नहीं, बल्कि प्रायश्चित कर रही है।

जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पर्यटन मंत्री डॉ. महेश शर्मा व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ हरिद्वार में एक समारोह में संयुक्त रूप से उत्तराखंड में नमामि गंगे के तहत 250 करोड़ लागत की 43 योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दो वर्ष की लंबी कसरत के बाद आज पांच राज्यों में एक साथ नमामि गंगे के तहत 1500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। उत्तराखंड में अक्टूबर 2016 तक उक्त सभी परियोजनाओं का काम भी शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 2018 में ही गंगा को निर्मल बनाने का लक्ष्य तय किया है। नमामि गंगे का प्रथम चरण पूर्ण होने पर वह गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा किनारे पदयात्रा कर इसके नतीजों का निरीक्षण भी करेंगी।

• हर जिले में ग्राम स्तर तक होगा समितियों का गठन

गंगा की सुरक्षा का बीड़ा अब उसके किनारे रहने वाले लोग ही उठाएंगे। प्रदेश से लेकर ग्रामीण स्तर तक की गंगा समितियां गठित की जाएंगी। यह समिति गंगा के किनारे पौधे लगाएंगी, घाटों को सुंदर बनाएंगी, साथ ही गंगा यात्रा भी निकालेंगी।

सन्दर्भः- दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान

संपर्क करें:
पवन कुमार, सह-संपादक, जल चेतना, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की-247667, हरिद्वार, उत्तराखंड, मो.न. 9359729313